

प्रेषक,

राकेश शर्मा,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल निदेशालय,

देहरादून।

संख्या-53(1)/VI-I/2008-4(5)20C4

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2008

विषय:-जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के लिए ग्राम थानीगांव में सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट भवन निर्माण हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-53/VI-I/2008-2(12)2006 दिनांक 16 जनवरी, 2008 जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट देहरादून जिसकी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग देहरादून है तथा जिनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य एवं धनराशि वापस लेते हुए, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम निर्माण इकाई, देहरादून को पूर्व स्वीकृत आगणन के आधार पर प्रदान कर दिया जाय एवं शासनादेश संख्या-308/VI-I/2006 दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 जिसके द्वारा सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को नामित करते हुए कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया था, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट देहरादून के निर्माण का कार्य लो0नि0वि0 से कार्य आरम्भ न करने/शीघ्र पूर्ण करने में विफलता के दृष्टिगत वापस लेते हुए उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम निर्माण इकाई, देहरादून द्वारा पूर्व संस्तुत आगणन के आधार पर ही कार्य कराये जाने हेतु पूर्व संस्तुत आगणन की धनराशि रू0 752.50 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 225.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त कार्य के लिए दी गयी रू0 752.00 लाख (रुपये सात करोड़ बावन लाख मात्र) प्राक्कलन के एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 225.00 लाख (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को उनकी डी0सी0एल0 से आहरित कर नयी कार्यदायी संस्था के पक्ष में एक सप्ताह में चैक द्वारा अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

नई कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० निर्माण इकाई, देहरादून द्वारा सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट का निर्माण पूर्व स्वीकृत आगणन के आधार पर ही किया जायेगा तथा इसके लिये कोई पुनरिक्षित आगणन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

- 4- अब निर्माण कार्य में कोई टाइम ओवर टन एवं व्यस्त ओवर टन नहीं होगा।
- 5- कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के सम्बन्ध में थर्डपार्टी चेकिंग की व्यवस्था की जायगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय देय सेंटेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जाएगा।
- 6- शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग की अशा०प०सं०-915(P)/XXVII(3)/2008 दिनांक 31 जनवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-निजी सचिव, मा० खेल मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 5-वित्त अनुभाग-3,
- 6-महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, देहरादून।
- 9-मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10-एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।